2019 का फैसला

लेखक - नीरा चंदोके (दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर)

निबन्ध खण्ड

द हिन्दू

27 मई, 2019

"मतदाता कोई ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो नई अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण से उत्पन्न असुरक्षा से उनकी रक्षा करे।"

2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शानदार जीत पर एक बड़ी बात पहले ही कही और लिखी जा चुकी है कि वह क्यों जीते और कांग्रेस इतनी बुरी तरह क्यों हार गई। फिर भी यह परिणाम आश्चर्यचकित करता है। श्री मोदी ने प्रमुख रोजगार के नुकसान, एक गंभीर कृषि संकट, अल्पसंख्यकों का हाशिए पर चले जाना और समाज के ध्रुवीकरण की अवधि के दौरान सरकार का नेतृत्व किया, जिसके बाद इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता में फिर से चुना। आखिर पूरे वर्ग और जाति के मतदाताओं द्वारा इन्हें फिर से चुनने के पीछे का रहस्य क्या है?

एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति

अगर ध्यान दें, तो हम पाएंगे कि पिछले पांच वर्षों में दुनिया भर की राजनीति में – उदाहरण के लिए, अमेरिका, रूस, तुर्की, फिलीपींस, हंगरी, पोलैंड और ब्राजील में, हमें एक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, जिसे सत्तावादी लोकलुभावनवाद कहा जाता है। लोकलुभावनवादी लोकतंत्र के विरोधी नहीं होते हैं, वे अक्सर विशाल जनादेश के साथ चुने जाते हैं। एक बार निर्वाचित होने के बाद, सत्तावादी लोकलुभावनवादी उन संस्थाओं और प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हैं जो सत्ता के अभ्यास –नागरिक समाज, मीडिया, शक्तियों का पृथक्करण और एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर लगाम लगाने का प्रयत्न करते हैं। वे लोकतांत्रिक शासन की जटिल और श्रमसाध्य प्रक्रियाओं से अधीर हैं।

दूसरा, सत्तावादी नेता मौजूदा कुलीनों को भ्रष्ट बताते हुए सत्ता पर कब्जा करते हैं। वे स्वयं इस अभिजात वर्ग का हिस्सा हो सकते हैं – चाहे वो एक अमीर डोनाल्ड ट्रम्प हो या नरेंद्र मोदी हो, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात में 12 से अधिक वर्षों तक सत्ता संभाली थी। तीसरा, सत्तावादी लोकलुभावनवादी नेता संसद में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित सवालों का जावाब देने के बजाय सीधे तौर पर एक अपरिपक्व और अस्थिर इकाई अर्थात् 'लोगों से' बात करना पसंद करते हैं। चौथा, लोकलुभावनवादी नेताओं ने अप्रवासियों और अल्पसंख्यकों जैसे समूहों को 'गैर-लोगों' के रूप में खारिज कर दिया।

इस बार विपक्षी नेताओं को श्री मोदी की तेजी से बदलती बयानबाजी के साथ तालमेल रखना असंभव लग रहा था। चुनाव प्रचार करते समय कई त्रुटियों के बावजूद, विपक्ष पर्याप्त रूप से या समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वह 'चौकीदार' से बालाकोट में स्थानांतरित हो गए और गैर-भाजपा नेताओं के पास यह पूछने का समय नहीं था कि आखिर पुलवामा हमला भारत की धरती पर हुआ कैसे? सर्वोत्कृष्ट सत्तावादी लोकलुभावनवादी नेता हुकूमत जताना पसंद करता है। वह खुद को एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, परम्पराओं को तोड़ता है और अपने नियम खुद बनाता है।

तो अब सवाल उठता है कि लोकतंत्र में मतदाता एक मजबूत व्यक्ति द्वारा शासन का विकल्प क्यों चुनता है? शायद वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं, जो उन्हें उदारीकरण और वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न निरंतर असुरक्षा की भावना से उनकी रक्षा कर सके। भारत में दोनों प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से 1991 में शुरू किया गया था। 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, वह अमेरिका में रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर द्वारा कल्याणकारी स्थिति को वापस लाने के लिए चिह्नित की गई थी। उनके लिए एक मुक्त बाजार सभी समस्याओं का जवाब था। बाजार की पौराणिक कथाओं को एक बार फिर से स्वीकार किया गया और इसके अन्याय को भुला दिया गया।

बाजार की जाँच

द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन (1944) में कार्ल पोलानी ने हमें बताया था कि बाजार शोषक सामाजिक संबंधों पर आधारित है, यह लोगों को निराश करता है और उनके दुख का कारण बनता है। बाजार की वजह से मजदूर-वर्ग के संघर्ष का उदय हुआ। ये आंदोलन बाजार को फिर से अपनी स्थिति में स्थापित करने में कामयाब रहे। किसी को बाजार का प्रभारी होना चाहिए था क्योंकि बाजार को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, यह सामाजिक और आर्थिक जीवन को नष्ट कर देगा।

उत्तर औपनिवेशिक कुलीन वर्ग ने उन बाजार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिन्हें शाही शक्तियों द्वारा एकाधिकृत कर दिया गया था। लेकिन 1990 के दशक में बाजार ने प्रभुत्व और वैधता हासिल कर ली। इस बार विचारधारा और इस प्रणाली की प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए कोई श्रमिक वर्ग नहीं था। इसका भी नाश हो गया था। भारत में, अनुबंधित श्रमिक को संगठित श्रमिक वर्ग में पेश किया गया था। इससे जबरदस्त असुरक्षा उत्पन्न हुई। सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण कर दिया गया और श्रमिकों को सड़क पर फेंक दिया गया। यहाँ वे असंगठित मजदूर वर्ग की उन श्रेणियों में शामिल हो गए, जिनका जीवन चिंताओं से भरा पड़ा था। भारत सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया, लेकिन इन उद्यमों के निचले स्तरों में, युवाओं को रोजगार की गारंटी नहीं दी गई।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्थव्यवस्था के पतन से उन लोगों को फायदा हुआ जो तकनीक के नए तरीकों और काम करने के नए तरीकों में बदलाव करने में कामयाब रहे। लेकिन इस प्रक्रिया में, वर्गों के बीच असमानता एक खतरनाक हद तक गहरा गई। जिन लोगों को छोड़ दिया गया था, उनमें बेहतर जीवनशैली और संपन्न लोगों की शानदार जीवनशैली पर नाराजगी की आकांक्षाएं पैदा हुईं। असुरक्षा, आकांक्षाओं और आक्रोश के साथ संयुक्त, इच्छा और सामाजिक ईर्ष्या की राजनीति को बढ़ावा दिया गया।

सत्ताधारी लोकलुभावनवादी नेताओं द्वारा कुलीन वर्ग के खिलाफ रोष दर्शाया गया और उन्होंने विरासत में मिले विशेषाधिकारों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। इन सबसे ऊपर, हमने देखा कि लोकलुभावनवादी नेताओं ने अज्ञात जनभीत (जेनोफोबिक, xenophobic) राष्ट्रवाद का निर्माण करने के लिए नाराजगी जताई और हम कुछ उदासी के साथ प्रगतिशील राजनीति के पीछे हटने के साक्षी बने।

फिराक की सावधानी

अस्पष्ट वर्ग की स्थिति और असुरक्षा, एक बेहतर जीवन और सामाजिक सम्मान की इच्छा, हताशा और सामाजिक ईर्ष्या की राजनीति को जेनोफोबिक राष्ट्रवाद की एक परियोजना के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रवाद की इस मनोदशा में जो कोई भी हमारे जैसा नहीं है वह शत्रु बन जाता है जिसने भूमि और संसाधनों को विनियोजित किया है। भले ही बहुसंख्यक भारतीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित अपराधों में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन वे इन अपराधों से पीड़ितों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं और यदि कोई किसी भी असहिष्णुता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कैंडल लाइट जुलूस निकालते हैं तो उन्हें विकृत तरीके से वर्गीकृत किया जाता है।

हमारे अपने लोग अपने ही देश में अजनबी हो गए हैं। कवि फिराक गोरखपुरी ने प्रसिद्ध रूप से लिखा था: सर जमीन-ए-हिंद पर आवाम-ए-आलम के फिराक/काफिले बसते रहे/हिंदोस्तान बनता गया (भारत प्रवास की क्रमिक लहरों द्वारा एक विविधता युक्त समाज के रूप में बनाया गया)। आज वे लोग जिनके पूर्वज इस भूमि में बस गए थे, जिनका श्रम विरासत का निर्माण करने के काम आया था और जो मरते समय इसी भूमि का हिस्सा बने थे, उन्हें विदेशियों के रूप में जाना जाता है।

श्री मोदी की मजबूत छवि लोगों को चिंता और आकांक्षाओं से उबारने के लिए आश्वस्त कर रही है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही है। शोधकर्त्ताओं ने हमें बताया कि आज दक्षिणपंथी लोकलुभावनवादी लोगों के लिए श्रमिक वर्ग वोट करते हैं। एक समय ऐसा था जब हमारे पास एक सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य था, लेकिन अब हमारे पास एक सत्तावादी लोकलुभावनवादी नेता हैं, जो अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इनके पास संसदीय लोकतंत्र की थकाऊ प्रक्रियाओं के लिए धैर्य नहीं है। थॉमस हॉब्स ने 17वीं शताब्दी में लिखा था कि सभी लोग आत्म-संरक्षण चाहते हैं। वे सुरक्षा के बदले एक शक्तिशाली नेता को अपना अधिकार देने को तैयार हैं।

वैश्वीकरण का सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव

सकारात्मक

1. **आधारभूत-संरचना का विकास:** वैश्वीकरण से विभिन्न राष्ट्रों के आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं; जैसे – औद्योगिक शक्ति के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगा है, विद्युत ऊर्जा, सड़कों, नये रेलमार्गों, नव-बन्दरगाहों, वायु परिवहन तथा दूर संचार का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया है।
2. **बाजारों का विस्तार:** वैश्वीकरण में व्यावसायिक संस्थाओं का आकार बहुत विशाल होता है तथा व्यावसायिक क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है, जिसके कारण इन संस्थाओं को सम्पूर्ण विश्व में व्यवसाय की छूट मिल जाती है तथा बाजारों का विस्तार होता जाता है।
3. **पर्यावरण के प्रति सजगता:** वैश्वीकरण व्यवसाय के वातावरणीय घटकों की विविधता को बढ़ाता है। इससे सैन्य सन्तुलन, संसाधनों के हस्तान्तरण की सुविधाओं, व्यापारिक सम्बन्धों, दूसरे राष्ट्र की जनसंख्या, जलवायु, बीमारियों, औषधियों, अस्त्र-शस्त्र व्यापार तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा लागतों पर पूर्ण रूप से ध्यान आकृष्ट हो जाता है, जो अन्ततः सभी राष्ट्रों के लिए लाभप्रद होता है।
4. **श्रम, पूँजी एवं सूचना प्रौद्योगिकी का स्वतन्त्र प्रवाह:** वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप सभी सम्बद्ध राष्ट्रों में उन्नत गुणवत्तायुक्त सूचना एवं तकनीकी, योग्य एवं अनुभवी, कार्मिक तथा कार्यशील पूँजी का स्वतन्त्र प्रवाह होता है, जिससे अर्थव्यवस्था को संबल मिलता है।
5. **स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा का विकास:** इस प्रक्रिया के अन्तर्गत, आयात-निर्यात नीति को पूर्ण प्रोत्साहन बिना कोई बाधा उत्पन्न किये हुए प्रदान किया जाता है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म मिलता है।
6. **उत्पादन क्षमता का स्वतन्त्र निर्धारण:** वैश्वीकरण का यह प्रभाव होता है कि उत्पादन क्षमता का निर्धारण, स्वतः ही बाजार शक्तियों के द्वारा होता रहता है तथा समय की बचत भी होती है।
7. **उपयुक्त उत्पादन एवं व्यापार ढाँचे का चयन:** इसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक-सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु के उपयुक्त उत्पादन एवं व्यापारिक-संरचना का चयन करने के लिए स्वतन्त्र होता है।
8. **व्यवसाय का स्थानान्तरण सम्भव:** वैश्वीकरण के कारण, आपातकालीन परिस्थितियों के अन्तर्गत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यवसायों को अपने यहाँ स्थानान्तरित कराने में सहायता करता है, ताकि समाप्ति के पश्चात् वे व्यवसाय पुनः मूल राष्ट्र में हस्तान्तरित हो सकें।
9. **निर्माण संयन्त्रों की बहुलता:** वैश्वीकरण की नीति को अपनाने से एक ही राष्ट्र के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक निर्माण संयन्त्र स्थापित हो जाते हैं, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलता है तथा उनके उत्पादन का लाभ सम्पूर्ण या एक विस्तृत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है ।
10. **स्वदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों का विकास:** वैश्वीकरण के पश्चात् भारत में स्वदेशी, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना का दौर चल रहा है। आई.सी.आई.सी.आई., रिलायन्स, एच.डी.एफ.सी., आई.डी.बी.आई., कोटक महिन्द्रा आदि निगम अब विदेशों तक अपने क्षेत्र का विस्तार करने में लगे हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी संबल मिला है।
11. **अन्य प्रभाव:**
    (i) भुगतान सन्तुलन सकारात्मक होने लगा है।
    (ii) सामाजिक क्षेत्रों; जैसे – चिकित्सा, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि पर भारी विनियोजन सम्भव हो पाया है।
    (iii) रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से बचत एवं विनियोग में भी भारी वृद्धि हुई है।
    (iv) राष्ट्रीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर सुधार होता जा रहा है।
    (v) सरकार, समाज, संगठन तथा कार्मिकों के मध्य परस्पर मधुर सम्बन्ध बने हैं।
    (vi) बहुराष्ट्रीय निगमों के आगमन के कारण देश की बहुमुखी प्रतिभाओं का पलायन रुका है।

वैश्वीकरण नीति के नकारात्मक प्रभाव:

I. व्यवसाय पर दुष्प्रभाव:

वैश्वीकरण के व्यवसाय पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं:

(1) वैश्वीकरण से गलाकाट प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है और इससे अर्थव्यवस्था को धक्का लग सकता है।

(2) लघु एवं कुटीर उद्योगों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना प्रबल हो जाती है। इससे क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा मिलता है।

(3) स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण निर्यातों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इससे आयातित वस्तुएँ बहुत महँगी हो जाती हैं।

(4) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निरन्तर बढ़ोत्तरी हानिकारक बन जाती है क्योंकि स्थानीय व्यावसायिक तथा औद्योगिक संगठनों पर बाह्य संस्थाओं का नियन्त्रण होने लगता है।

(5) संस्थाओं के अधिग्रहण करने या संविलयन करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे छोटी संस्थाओं के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है।

(6) बड़े या बहुराष्ट्रीय संगठन आर्थिक क्षेत्र पर एकाधिकार करने की स्थिति में आ जाते हैं। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भुगतान सन्तुलन नकारात्मक स्थिति में आने की सम्भावना बढ़ जाती है।

सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव:

(1) दैनिक जीवन की वस्तुओं के लिए सम्पूर्ण विश्व खुली अर्थव्यवस्था के अनुरूप होने पर देश में ऐसी वस्तुए महँगी होने लगेंगी।

(2) उद्योगों में यन्त्रीकरण बढ़ने से बेरोजगारी की सम्भावना बढ़ जाती है, जो राष्ट्र के हित के लिए ठीक नहीं है।

(3) बहुराष्ट्रीय निगमों को महत्व प्रदान करने से विकासशील राष्ट्रों की योजनाओं की प्राथमिकता प्रभावित होगी और इससे देश का सन्तुलित आर्थिक विकास भी प्रभावित हो सकता है।

(4) विदेशी कम्पनियों के द्वारा भारतीय उद्योगों के साथ भेदभाव प्रारम्भ हो गया है। उन्हें मिलने वाली छूटों से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कारण वंचित किया जा रहा है।

(5) बिना सरकारी संरक्षण के अनेक घरेलू व्यवसाय या व्यावसायिक संस्थाएँ बर्बाद या बन्द होने की कगार पर आ सकती हैं।

(6) वैश्वीकरण की नीति लागू होने के उपरान्त समस्त राष्ट्र व्यावसायिक बाजारों की श्रेणी में आ जायेंगे, जिससे उनकी सार्वभौमिकता पर आँच आ सकती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. भारत में आर्थिक उदारीकरण जुलाई, 1991 के पश्चात् शुरू किया गया।
2. उदारीकरण प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के संरक्षण में हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

1. Consider the following statements:

1. Economic liberalization in India started after July, 1991.
2. Liberalization was done under the assistance of Prime Minister P.V. Narasimha Rao.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- हाल ही में भारत में संपन्न 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को दरकिनार कर राष्ट्रवाद और आंतरिक सुरक्षा के नाम पर पुनः एक सशक्त प्रधानमंत्री को चुना। यह किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Recently, in the Lok Sabha elections held in India in the year 2019, the voters opted for a strong prime minister in the name of nationalism and internal security, bypassing the basic needs like employment, health education. What kind of change does this reflect? Discuss. (250 Words)

नोट : 25 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(b) होगा।

Committed To Excellence